

**Demand to take suitable legislative measures for economic and social
empowerment of women in the country**

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : महोदय, अफसोस की बात है कि लाखों-करोड़ों की संख्या में हमारी बहनें आज भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं होने के कारण समाज एवं परिवार में अपेक्षित एवं कमजोर स्थिति में हैं तथा परिवार में कई प्रकार के मानसिक क्लेश, शोषण एवं अपमान को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अपने बच्चों के हित के कारण सहने को बाध्य हैं। गोआ में पुर्तगाली कानून के मुताबिक पत्नी को पति की चल एवं अचल सम्पत्ति में कानूनन बराबर की भागीदारी प्राप्त है। इससे वहां पर महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अन्य कई प्रदेशों की तुलना में अधिक मजबूत है, जिसके कारण गोआ में महिलाओं पर घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न संबंधी मामलों का प्रतिशत भी अन्य प्रदेशों के तुलना में कम है। मेरा अनुरोध है कि सरकार यदि इस प्रकार का विधेयक लाकर देश की महिलाओं के हित में पूरे देश में इस कानून को लागू कर दे तो महिलाओं को पति की चल एवं अचल सम्पत्ति में बराबर का कानूनी हक मिल सकेगा। इससे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा तथा अनेक प्रकार के घरेलू शोषण से उसे मुक्ति मिल सकेगी। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इस कानून की आज अहम आवश्यकता है। अतः सरकार से अपेक्षा है कि वह इस दिशा में समुचित कदम उठाए।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I associate myself with this issue.

Demand for comprehensive change in Air India's management

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, the concept of the management of the Air India must undergo a drastic change if the airline has to be put on the path of progress in future. One important reform would be to institute a highly competent body to determine a criterion for selection of a person at the helm. The whole exercise has to be based on merit and suitability. It will no longer hold good to put a civil servant from the Ministry concerned as in charge of the enterprise on the basis of his/her seniority.

Presently, the Maharaja is being described variously. The most appropriate description is that it is a cashless Maharaja.

One wonders how the Maharaja came to this pathetic position. While many factors could be responsible, the chief reason is the mismanagement that was experienced over a long period of time in the Air India enterprise.

The sordid state of affairs of the Air India which was once a prestigious national asset is no reflection on the efficiency of the Minister in charge, for he has been seen widely to improve the things in the system.

While the hon. Prime Minister will do everything possible to rejuvenate the Air India and help it to regain its position as a national asset, certain crucial measures need to be taken to reform the inner dynamics of the airline. Thank you.

**Concern over plight of Indian fishermen fishing off the coast of
Kachhatheevu in Palk Strait**

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to bring to the attention of the Minister of External Affairs to the plight of Indian fishermen fishing in the Palk Strait between India and Sri Lanka. This week, twenty Indian fishermen were arrested by Sri Lankan Navy when they were fishing off the

coast of Island of Kachhatheevu. This matter should immediately be taken up with the Government of Sri Lanka, and their release should be secured at the earliest. Kachhatheevu was gifted by India to Sri Lanka. Today, our innocent fishermen are harassed by Sri Lanka for fishing off the coast of Kachhatheevu. The agreement on Kachhatheevu should be renegotiated and the fishing rights of Indian fishermen should be restored. Sri Lanka should be strongly told to desist from harassing Indian fishermen. Presence of Indian Navy and coast guard should be considerably increased in Palk Strait for the safety and security of Indian fishermen fishing in the territorial waters of our country. As a permanent solution to this problem, our fishermen may be issued special identity cards, and they may be simply asked to go back to our territorial waters in case of mistakenly entering the territorial waters of Sri Lanka. An agreement should be reached with that country in this regard. I hope that the Minister will take immediate steps in this regard for the safety and security of Indian fishermen. The only solution to this long-standing problem is to retrieve Kachhatheevu.

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with it.

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with it.

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Shyamal Chakraborty. Not present. Shri Kalraj Mishra.

Need to extend date of debt waiver scheme for farmers in the country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं सदन का ध्यान किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूँ। 12 जून को वित्त मंत्रालय ने आर.बी.आई. को एक पत्र लिखकर कर्ज माफी की एक योजना पर कार्यवाही करने को कहा। इस कर्ज माफी योजना के तहत तीन चौथाई कर्ज चुकाकर एक चौथाई कर्ज माफ किया जाना था, अर्थात् जो किसान 30 जून तक बकाया कर्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा देगे तो उनका बचा हुआ 25 प्रतिशत कर्ज माफ किया जाएगा। यह योजना उन किसानों के लिए भी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2007 तक कर्ज लिया था, लेकिन इसका भुगतान 29 मार्च, 2009 तक नहीं किया था। साथ ही इसे श्रेणी में आने वाले किसान पिछले वर्ष कर्ज माफी की योजना में नहीं होने चाहिए थे। केन्द्र सरकार के निर्देश पर आर.बी.आई. ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए और यह भी कहा कि बकाये राशि पर किसानों से कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। परन्तु इस कर्ज माफी योजना का लाभ किसान नहीं उठा पाए। पहले तो इस योजना में सरकार ने कर्ज चुकाने का बहुत ही कम समय दिया और जब तक किसान इस योजना को समझ पाता, इस योजना की तारीख ही खत्म हो गई तथा इस योजना का भली-भांति प्रचार भी नहीं किया गया। देखने में यह आया है कि किसान को इस योजना के बारे में पता ही नहीं था और जिनको पता था वो भ्रमित थे।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस योजना की तिथि बढ़ाई जाए और इसका सही ढंग से प्रचार हो और भविष्य में इस तरह की योजनाओं में उक्त बातों का ध्यान रखे। धन्यवाद।

डा. सी. पी. ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Amir Alam Khan. Not present.

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 9th July, 2009.